

अपराध-वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि

द्वारा
डॉ. मृदुल श्रीवास्तव

१८५८ का प्रशासनिक ब्लूप्रिंट

ईस्ट इंडिया कंपनी के ३० वर्षों के प्रशासन और सुधारों का ऐतिहासिक विश्लेषण



Canal Map

Canal

Canal

"देश के आंतरिक प्रशासन को सुधारने के लिए अपनाए गए प्रमुख उपायों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण।" - १८५८ का ज्ञापन

१८२८-१८५८: भारत के प्रशासन में प्रमुख सुधार

१८५८ के एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ पर आधारित, यह इन्फोग्राफिक पिछले ३० वर्षों में राजस्व, सार्वजनिक निर्माण और सामाजिक सुधारों में हुए विकास का लेखा-जोखा है।

बुनियादी
ढांचा और
सार्वजनिक
कार्य

गंगा नहर

सिंचाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक

४५
लाख एकड़ क्षेत्र में
सिंचाई की क्षमता

पेशावर

जुमना नहरें (पश्चिमी)
४४५ मील

अकाल के दौरान
फसल सुरक्षा और
राजस्व वृद्धि

कलकत्ता

ग्रेंड ट्रंक रोड १५०० मील लंबी
निर्बाध संचार

कलकत्ता से पेशावर तक सड़कों का विस्तार
और पुलों का निर्माण किया गया

राजस्व प्रणालियों में सुधार

रैयतवाड़ी और ग्राम-आधारित प्रणालियों के माध्यम से
किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास

सामाजिक और न्यायिक सुधार

अमानवीय सामाजिक
प्रथाओं का उन्मूलन



सती प्रथा



दास प्रथा



कन्या भ्रूण हत्या

कानूनी रूप से प्रतिबंधित

न्यायिक प्रणाली का सरलीकरण

- स्थानीय अदालतों का विस्तार
- भारतीय दंड संहिता की नींव रखी गई

‘ठगी’ (Thuggee) का पूर्ण दमन

ठगों के संगठित गिरोहों को जड़ से खत्म
कर सड़कों को सुरक्षित बनाया गया



MEMORANDUM,

&c., &c.

At this time, when a calamity unexampled in the history of British India has excited an unusual amount of interest in Indian affairs, while the statements publicly made, and the opinions expressed, concerning the administration of the Indian Government strikingly manifest the deficiency of correct information on the subject; a brief survey of the principal measures which have been hitherto adopted for improving the internal government, and ascertaining the physical and mental condition of the inhabitants, may be serviceable in removing false impressions, and in supplying materials for a deliberate judgment.

It may be thought that this survey would most fitly commence from the last renewal of the powers of the East-India Company, with some modifications, in 1853; and it must be said that the years which have since elapsed have been marked by a degree of activity in every description of public improvement, not only greater than that exhibited previously, but unsurpassed, it is believed, in any country and in any

पृष्ठभूमि: १८५७ का 'अभूतपूर्व संकट'

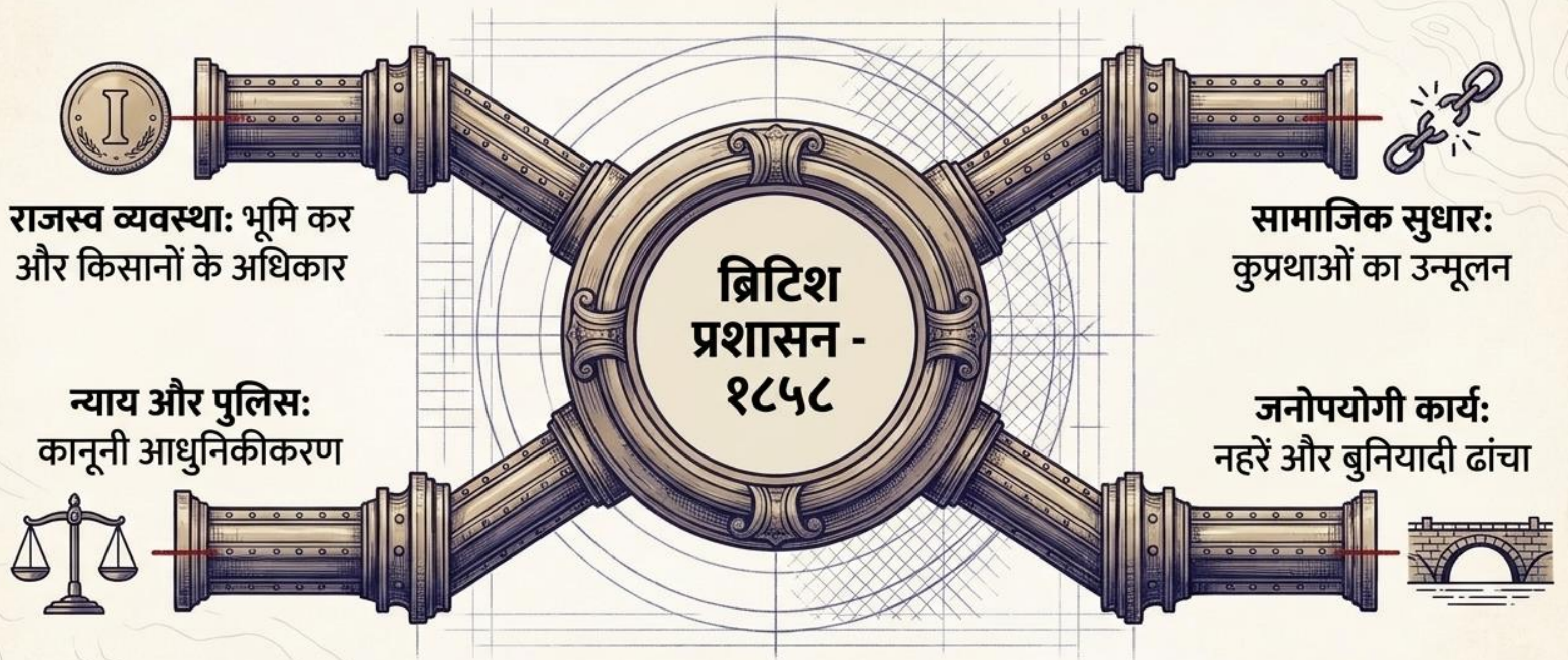
स्थिति: १८५७ के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के प्रशासन पर गंभीर सवाल।

उद्देश्य: ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सत्ता छिनने से पहले ब्रिटिश संसद के समक्ष अपने सुधारों का बचाव।

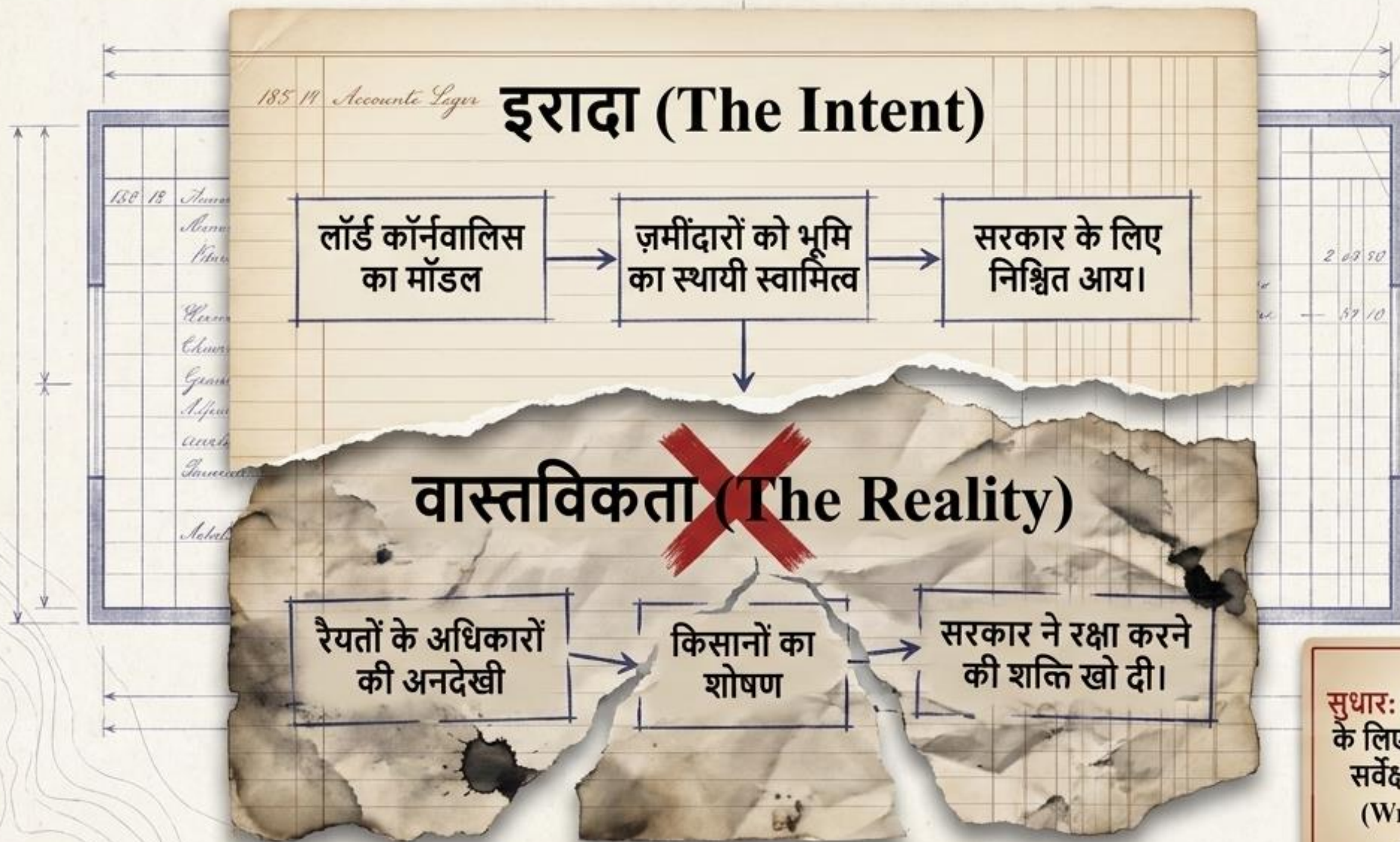
दस्तावेज़: १८५३ के बाद के प्रशासन पर केंद्रित, लेकिन पिछले ३० वर्षों के व्यापक बदलावों का सारांश।

"गलतफहमियों को दूर करना और विचार-विमर्श के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करना।"

शासन के चार विषयगत स्तंभ



प्रारंभिक भूल: बंगाल का स्थायी बंदोबस्त



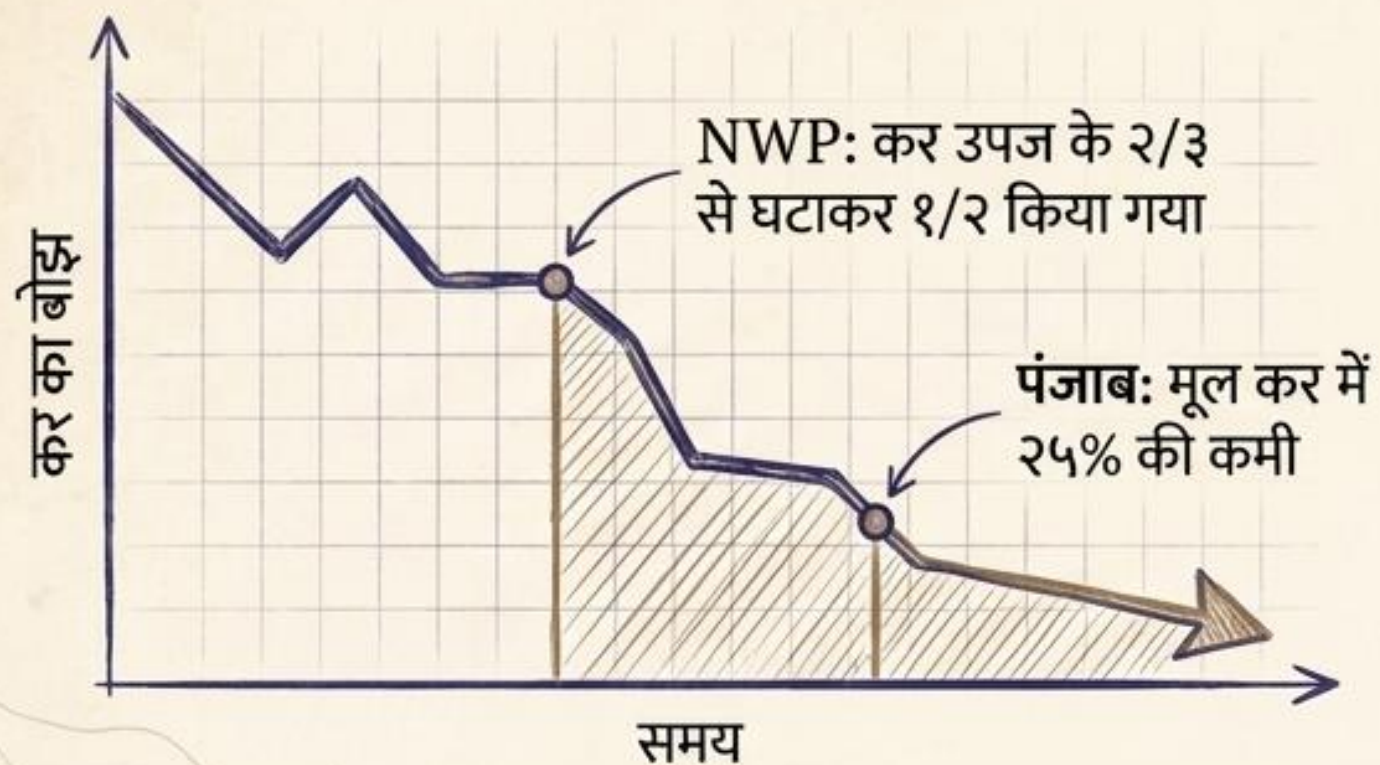
सुधार: इस गलती को ठीक करने के लिए बाद के प्रांतों में नए भूमि सर्वेक्षण और कानूनी अनुबंध (Written Engagements) अनिवार्य किए गए।

राजस्व प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण

Land Tenure Comparison Matrix

प्रणाली (System)	क्षेत्र (Region)	स्वामित्व (Ownership)	प्रमुख सुधार (Key Reforms)
स्थायी बंदोबस्त (Permanent)	बंगाल	ज़मींदार	रैयतों के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए बाद में विस्तृत सर्वेक्षण।
महालवाड़ी (Village System)	उत्तर-पश्चिम प्रांत और पंजाब	ग्राम समुदाय	३०-वर्षीय पट्टा; कर घटाकर शुद्ध उपज का आधा (१/२) किया गया।
रैयतवाड़ी (Ryotwari)	मद्रास और बंबई	वास्तविक कृषक (Cultivator)	सर थॉमस मुनरो का मॉडल; बंबई में ३०-वर्षीय निश्चित मांग लागू की गई।

कराधान और व्यापार में रियायतें



सीमा शुल्क (Customs)

अंतर्देशीय पारगमन शुल्क पूरी तरह समाप्त।
भारत अब वाणिज्यिक रूप से एक साम्राज्य
(One Empire) बन गया।



डाकघर (Post Office)

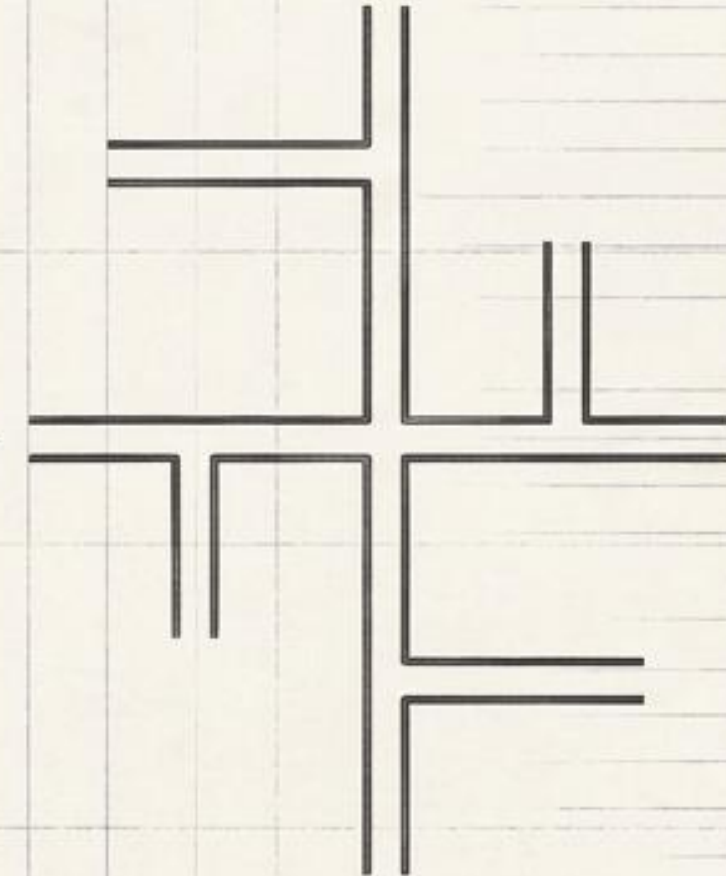
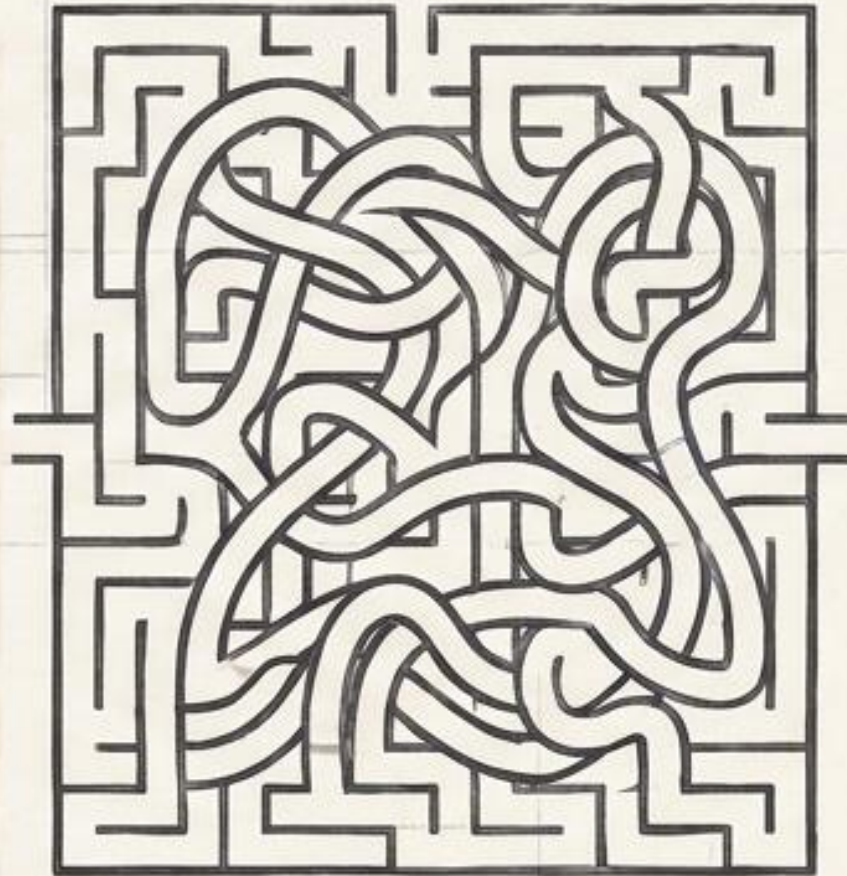
इंग्लैंड की तर्ज पर समान डाक दर - केवल
आधी आना (Half anna) में पत्र पूरे भारत
में।

न्यायपालिका: जटिलता से सरलता की ओर

कॉर्नवालिस प्रणाली

बेंटिक के सुधार और बाद (Post-1831)

- तकनीकी और अत्यधिक महंगी।
- पूरी तरह यूरोपीय न्यायाधीशों पर निर्भर।
- भयानक देरी और जटिल प्रक्रिया।



- देसी जजों (Native Judges) की नियुक्ति।
- फारसी भाषा का उन्मूलन; अदालतों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग।
- लॉ कमीशन (१८३३) द्वारा नई दंड संहिता (Penal Code) का निर्माण।

केस स्टडी: द पंजाब मॉडल

सर जॉन लॉरेंस की न्याय व्यवस्था



सस्ती और त्वरित: न्याय प्रदान करने के लिए सरल नियम (Brief, accessible rules)।



कोई तकनीकी जटिलता नहीं: जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के बिना सीधा और सुलभ न्याय।



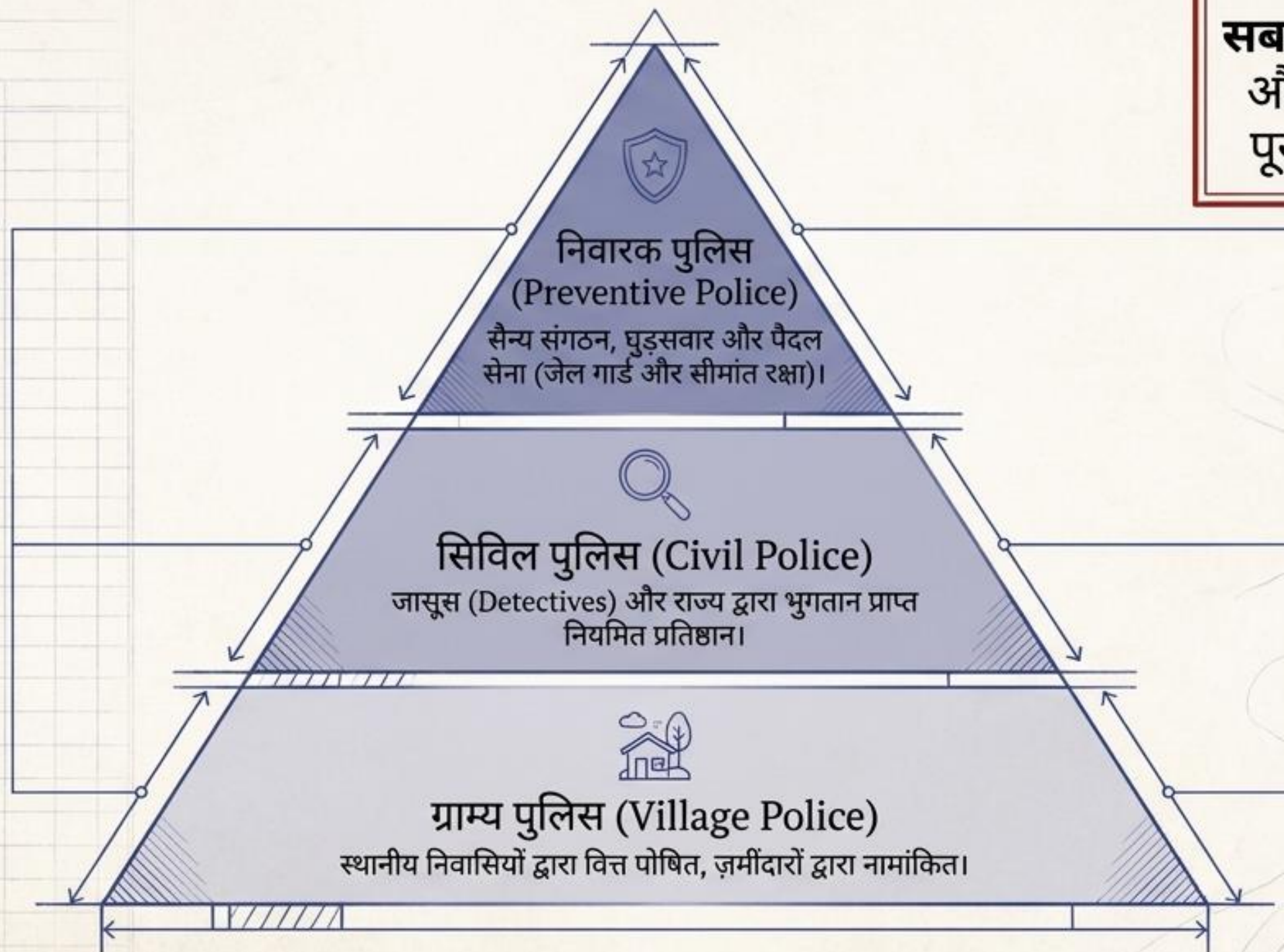
प्रत्यक्ष गवाही: वादियों और गवाहों का खुली अदालत में आमना-सामना (Confronted in open court)।

निष्कर्ष: इस मॉडल ने साम्राज्य के नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए न्याय का एक मानक स्थापित किया।

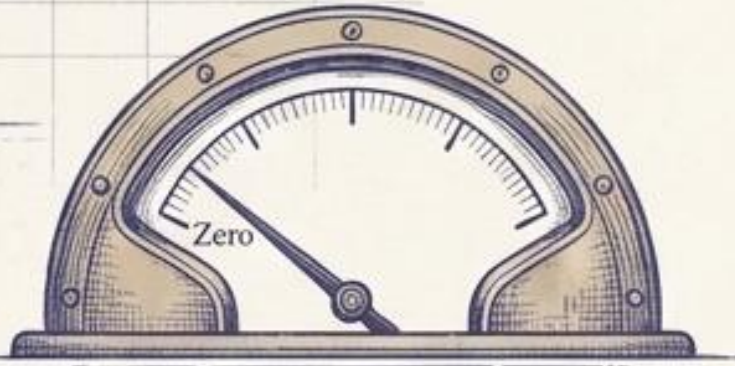
पुलिस सुधार: शक्तियों का पृथक्करण



सबसे बड़ा सुधार: राजस्व और पुलिस विभागों को पूरी तरह अलग करना।



अपराध उन्मूलन ट्रैकर: भाग १

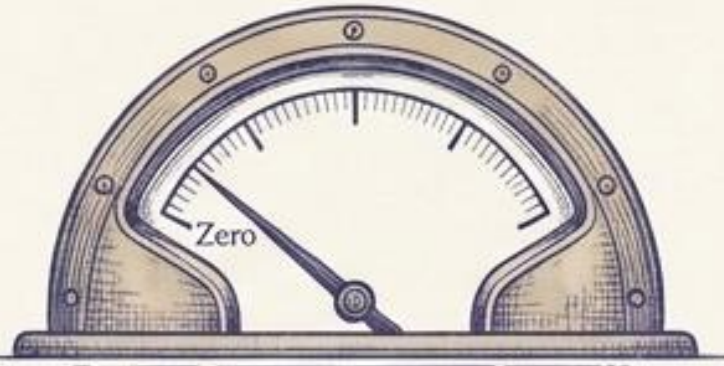


ठगी (Thuggee)

प्रकृति: धार्मिक हत्या और गुप्त लूट।

कार्रवाई: विशेष पुलिस विभाग और मुखबिर (Approver) प्रणाली का उपयोग।

परिणाम: पूरे भारत में पूरी तरह ससाया।

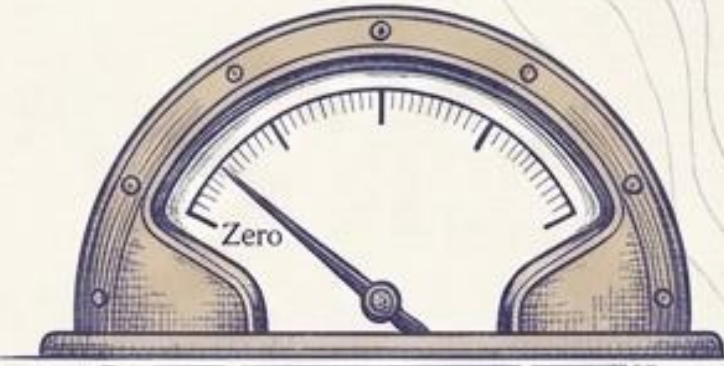


डकैती (Dacoitee)

प्रकृति: पेशेवर गिरोहों द्वारा संगठित लूट।

कार्रवाई: ठगी विरोधी समान रणनीतियों का प्रयोग।

परिणाम: उत्तर-पश्चिम प्रांत और बंबई में लगभग समाप्त।



समुद्री लूट (Piracy)

प्रकृति: अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले।

कार्रवाई: नौसैनिक शक्ति और संधियों का प्रयोग।

परिणाम: अरब सागर व्यापार के लिए पूरी तरह सुरक्षित।

सामाजिक सुधार ट्रैकर: भाग २

सती प्रथा

लॉर्ड डब्ल्यू. बेंटिन द्वारा इसे एक आपराधिक कृत्य (Criminal Offence) घोषित कर प्रतिबंधित किया गया।

गुलामी और मानवाधिकार

१८४३ में दास प्रथा का कानूनी दर्जा समाप्त। १८५० में धर्म परिवर्तन पर संपत्ति के अधिकारों की रक्षा।

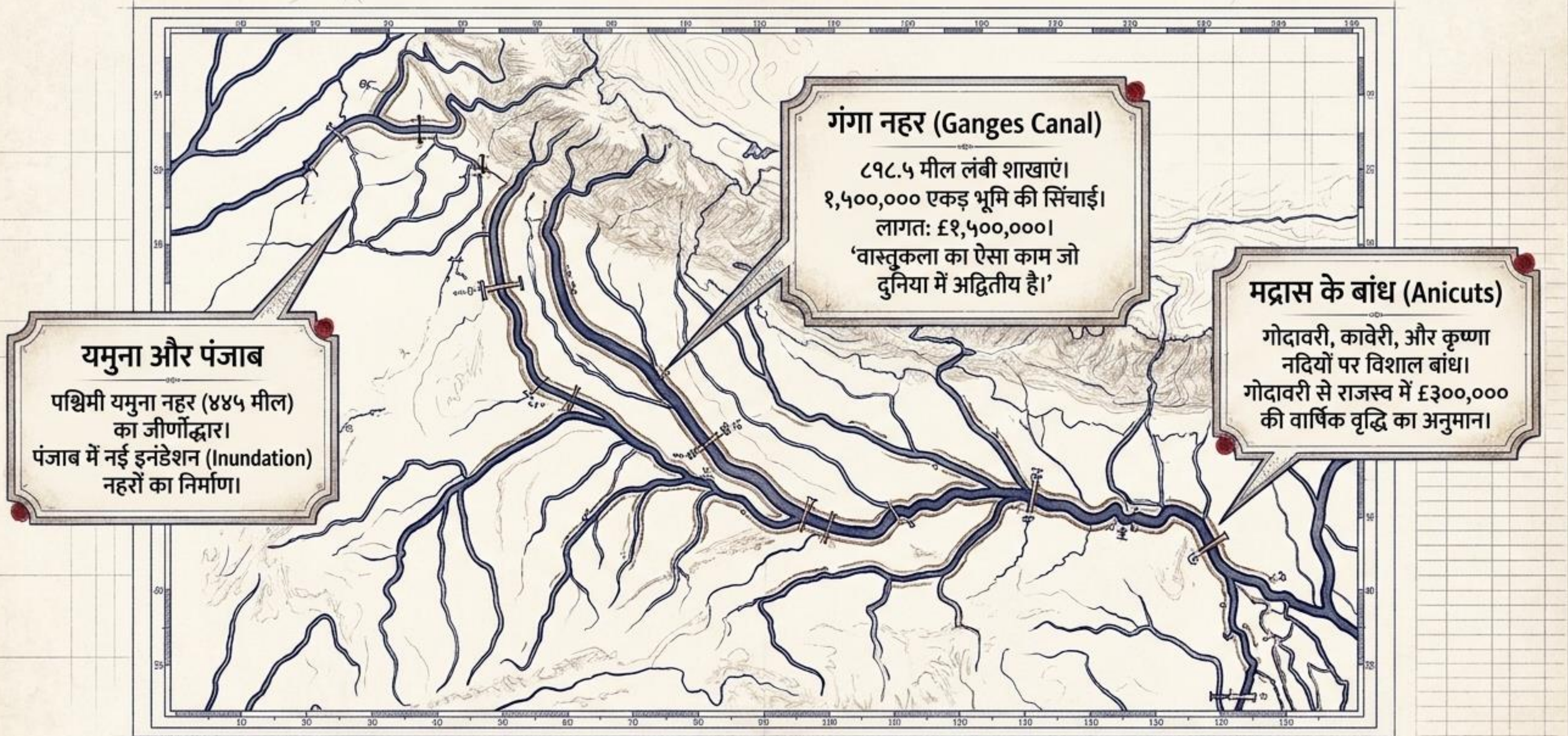
कन्या भ्रूण हत्या

जनगणना लागू करके और विवाह खर्च सीमित करके इस प्रथा को दबाया गया।

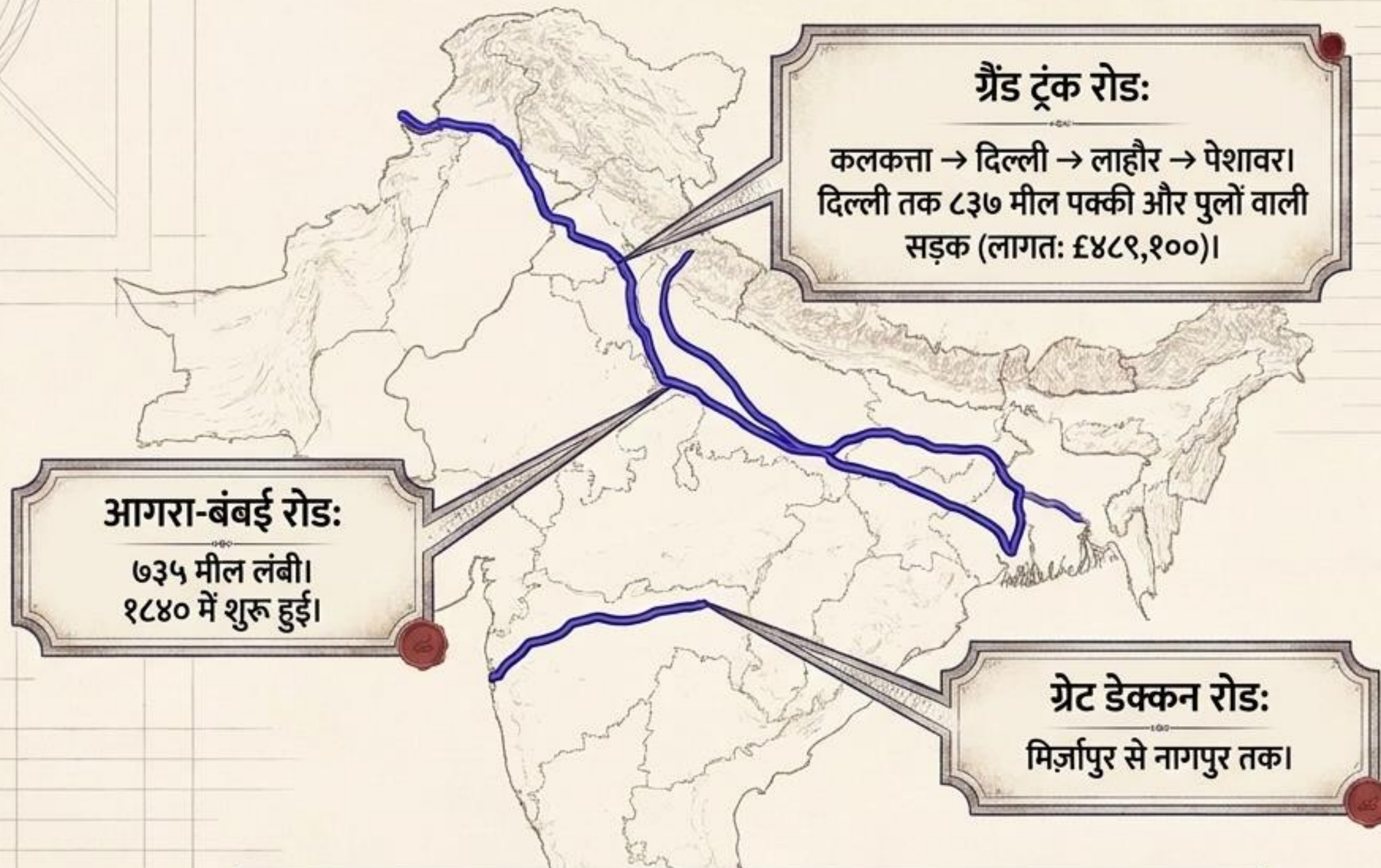
विधवा पुनर्विवाह

१८५६ का अधिनियम जिसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध बनाया।

जनोपयोगी कार्य: सिंचाई का जाल

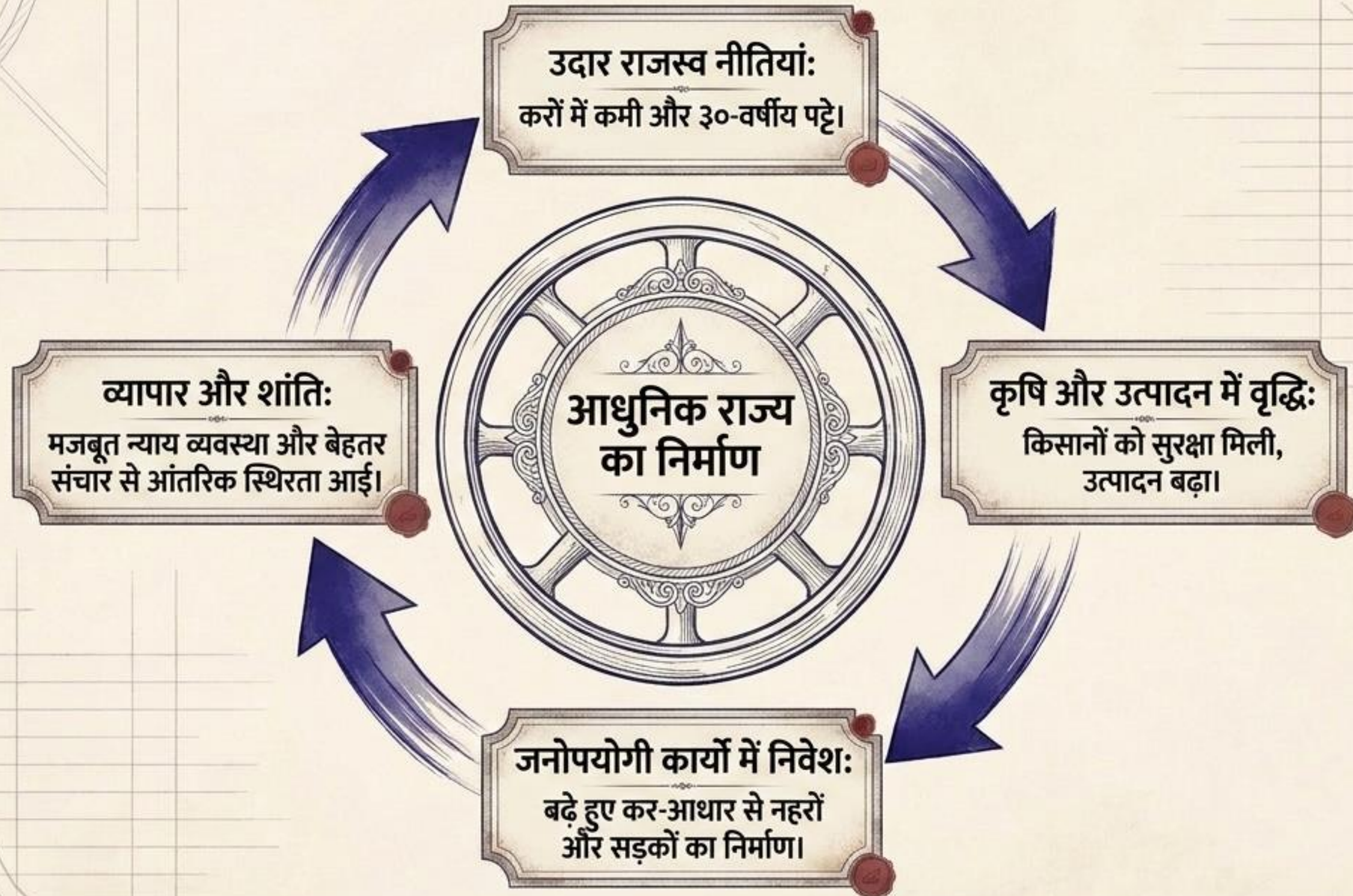


जनोपयोगी कार्य: आंतरिक संचार



"भारत में जहाँ परम आवश्यकता न हो, वहाँ स्थायी सड़कों का निर्माण
मूल शासकों की प्रथा नहीं थी।" - ब्रिटिश प्रशासन का दावा।

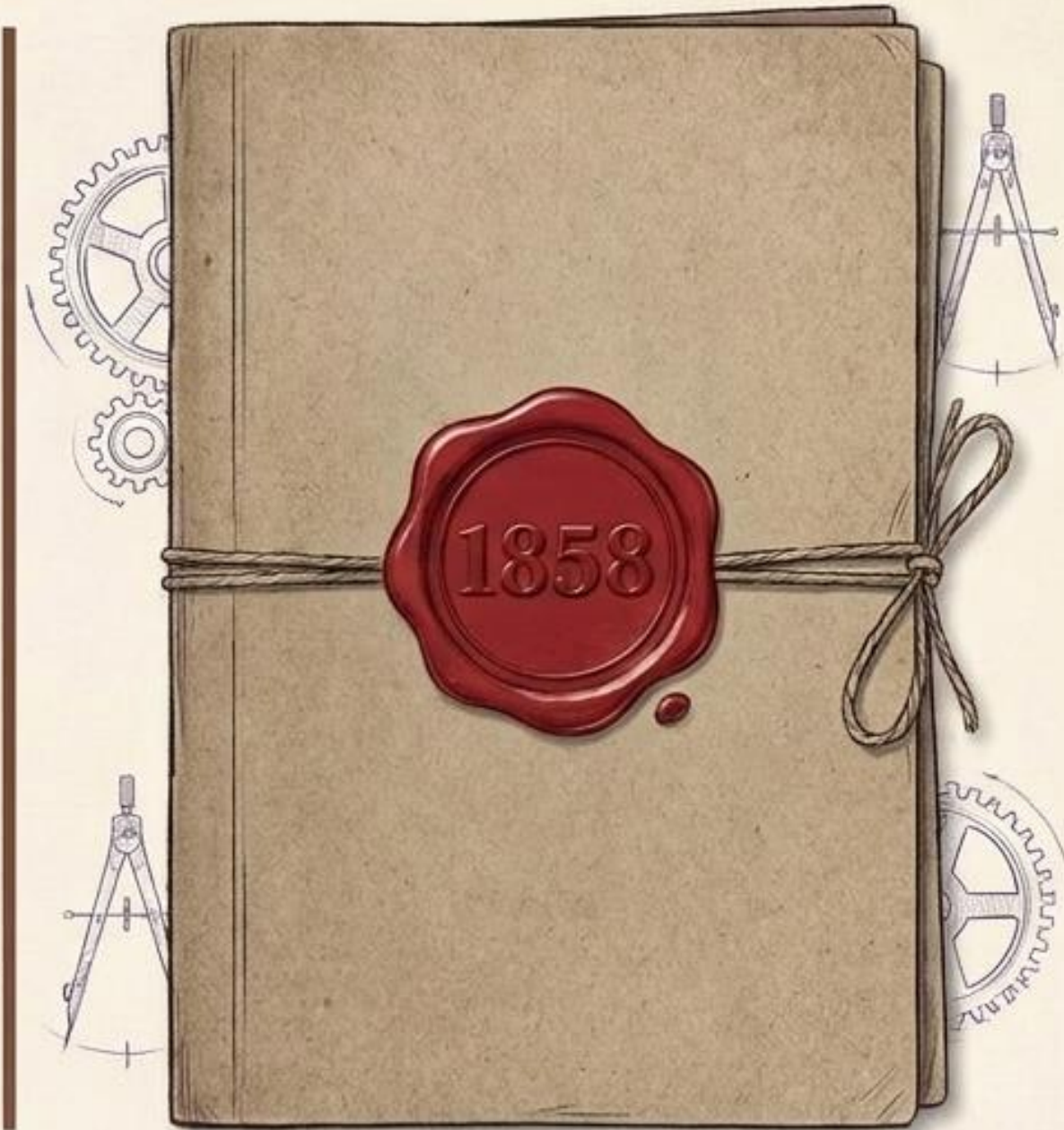
औपनिवेशिक प्रशासन का चक्र



निष्कर्ष: कंपनी का अंत, आधुनिक भारत की नींव

दस्तावेज़ का परिणाम

यह १८५८ का झापन ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग होने से नहीं बचा सका। भारत का प्रशासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया।



ऐतिहासिक विरासत

कंपनी के बचाव में सूचीबद्ध ये सुधार — भूमि कर प्रणाली, दंड संहिता, पुलिस पदानुक्रम, और नहर नेटवर्क — अगले ९० वर्षों तक और आधुनिक भारतीय गणराज्य में भी प्रशासनिक ढांचे का आधार बने रहे।

The architectural blueprint of 1858 outlasted its architects.